

# राज्य विधिज्ञ परिषद् उत्तराखण्ड, नैनीताल

## Bar Council of Uttarakhand, Nainital



मूल्य 2000/-रूपये  
(दो हजार रूपये मात्र)

डाक व्यय सहित  
(दो हजार पचास रूपये मात्र)

Latest Passport size  
photograph as given in  
Instruction No. 3,  
attested by the First  
Class Judicial  
Magistrate / Hon'ble  
Member of Bar  
Council of Uttarakhand

आवेदन पत्र क्रमांक .....सन् .....  
(एडवोकेटस अधिनियम, 1961 की धारा 25 एवं तत्सम्बन्धित धारा 24 के अनतर्गत)

श्रेणी- सामान्य/अनु0 जाति/अनु0 जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग .....

श्री.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....

के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

सेवा में,

सचिव,  
बार कौंसिल आफ उत्तराखण्ड,  
नैनीताल।

श्री .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....

निवासी .....का इस विनम्र आवेदन पत्र द्वारा

अत्यंत विनयपूर्वक निवेदन है कि:-

1. मैं आवेदक भारतीय हूँ मेरी आयु 21 वर्ष से अधिक है तथा बार कौंसिल आफ उत्तराखण्ड के एडवोकेटे हेतु प्रवेश पाने का प्रार्थी हूँ।

2. आवश्यक विवरण निम्नलिखित है:-

(क) नाम (अंग्रेजी में) SRI .....

(हिन्दी में) श्री .....

(ख) पिता का नाम (अंग्रेजी में) SRI .....

(हिन्दी में) श्री .....

3. जन्म तिथि .....(हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में उल्लिखित)

4. विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व क्या आवेदक स्नातक था ? (हाँ अथवा नहीं में निश्चित उत्तर दें).....

यदि स्नातक हो तो-

(i) विद्यालय का नाम जहाँ स्नातक शिक्षा प्राप्त की.....

(ii) प्राप्त श्रेणी व प्रतिशत .....

(iii) स्नातक अध्ययन में लगे समय (वर्षों में) .....

(iv) परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं स्नातक प्रमाण-पत्र की तिथि.....

(v) जिस वर्ग के लिये स्नातक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। कला, विज्ञान या वाणिज्य .....

5. विद्यालय का नाम जहाँ विधि पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त की एवं विश्वविद्यालय का नाम जहाँ से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की .....

- (i) विधि स्नातक की उपाधि का नाम जो प्राप्त किया .....
- (ii) शिक्षा सत्र जिसमें उपाधि प्राप्त की .....
- (iii) क्या विधि स्नातक की उपाधि व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्राप्त किया अथवा कक्षाओं की उपस्थिति द्वारा संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में जैसा कि बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों में व्यवस्थित है .....
- (iv) शिक्षा सत्र एवं वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम का अध्ययन प्रारम्भ किया .....
- (v) विधि पाठ्यक्रम के अध्ययन में कितना समय लगा .....
- (vi) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अध्ययन में लगे वर्षों की संख्या एवं उनके नाम .....
- (vii) परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं विधि स्नातक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की तिथि .....

### पंजीकरण शुल्क जमा किये जाने का माध्यम चालान/ड्राफ्ट

1. चालान की प्रति बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड की वैबसाइट से डाउनलोड करें।
2. चालान द्वारा जमा शुल्क की प्रति फॉर्म के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें।
3. चालान द्वारा भुगतान न कर पाने की स्थिति में ड्राफ्ट से भुगतान किया जा सकता है।
4. निम्न तालिका में से सम्बन्धित श्रेणी पर सही (✓) का चिह्न लगायें व श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्न मदों में जमा करायें।

सामान्य श्रेणी	अनुसूचित जाति	सामान्य श्रेणी, 40 वर्ष एवं अधिक	अनुसूचित जाति, 40 वर्ष से अधिक
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड फॉर्म शुल्क ₹0 2000/- पंजीकरण शुल्क ₹0 6000/- कुल शुल्क- ₹0 8000/-	बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड फॉर्म शुल्क ₹0 2000/- पंजीकरण शुल्क ₹0 3000/- कुल शुल्क- ₹0 5000/-	बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड फॉर्म शुल्क ₹0 2000/- पंजीकरण शुल्क ₹0 6000/- आयु सीमा शुल्क- ₹0 20000/- (पुरुष) आयु सीमा शुल्क- ₹0 15000/- (महिला) कुल शुल्क (पुरुष)- ₹0 28000/- कुल शुल्क (महिला)- ₹0 23000/-	बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड फॉर्म शुल्क ₹0 2000/- पंजीकरण शुल्क ₹0 3000/- आयु सीमा शुल्क (पुरुष)- ₹0 20000/- आयु सीमा शुल्क (महिला) - ₹0 15000/- कुल शुल्क (पुरुष)- ₹0 25000/- कुल शुल्क (महिला)- ₹0 20000/-
बार काउंसिल इण्डिया कलेक्शन फण्ड शुल्क- ₹0 150/-	बार काउंसिल इण्डिया कलेक्शन फण्ड शुल्क- ₹0 25/-	बार काउंसिल इण्डिया कलेक्शन फण्ड शुल्क- ₹0 150/-	बार काउंसिल इण्डिया कलेक्शन फण्ड शुल्क- ₹0 25/-
ऑल इण्डिया बार काउंसिल एडवोकेट वैलफेयर कमेटी शुल्क ₹0 3000/-	ऑल इण्डिया बार काउंसिल एडवोकेट वैलफेयर कमेटी शुल्क ₹0 3000/-	ऑल इण्डिया बार काउंसिल एडवोकेट वैलफेयर कमेटी शुल्क ₹0 3000/-	ऑल इण्डिया बार काउंसिल एडवोकेट वैलफेयर कमेटी शुल्क ₹0 3000/-
बार काउंसिल उत्तराखण्ड इस्टेब्लिसमेंट फण्ड फॉर एक्सीडेंट एण्ड डैथ क्लेम शुल्क ₹0 5000/-	बार काउंसिल उत्तराखण्ड इस्टेब्लिसमेंट फण्ड फॉर एक्सीडेंट एण्ड डैथ क्लेम शुल्क ₹0 5000/-	बार काउंसिल उत्तराखण्ड इस्टेब्लिसमेंट फण्ड फॉर एक्सीडेंट एण्ड डैथ क्लेम शुल्क ₹0 5000/-	बार काउंसिल उत्तराखण्ड इस्टेब्लिसमेंट फण्ड फॉर एक्सीडेंट एण्ड डैथ क्लेम शुल्क ₹0 5000/-
बार काउंसिल उत्तराखण्ड रजिस्ट्रेशन वैरिफिकेशन शुल्क ₹0 2500/-	बार काउंसिल उत्तराखण्ड रजिस्ट्रेशन वैरिफिकेशन शुल्क ₹0 2500/-	बार काउंसिल उत्तराखण्ड रजिस्ट्रेशन वैरिफिकेशन शुल्क ₹0 2500/-	बार काउंसिल उत्तराखण्ड रजिस्ट्रेशन वैरिफिकेशन शुल्क ₹0 2500/-
सम्पूर्ण शुल्क योग-18650/-	सम्पूर्ण शुल्क योग-15525/-	सम्पूर्ण शुल्क योग (पुरुष)-38650/- (महिला)-33650/-	सम्पूर्ण शुल्क योग (पुरुष)-35525/- (महिला)-30525/-

**सामान्य अभ्यर्थी द्वारा देय शुल्क**

1. पंजीकरण शुल्क के लिये 6000/- रुपये का भुगतान देने का बैंक ड्राफ्ट नं0 ..... तिथि .....
2. वैरिफिकेशन शुल्क के लिए 2500/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट नं0 ..... तिथि .....
3. रुपये 150/- का बैंक का नाम ड्राफ्ट नं0 ..... तिथि.....
4. नियम 40 के अन्तर्गत रुपये 3000/- का बैंक ड्राफ्ट नं0 ..... तिथि.....
5. स्टेब्लिसमेण्ट फण्ड रुपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट नं0 ..... तिथि.....
6. 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों हेतु रू0 2000.00/15000.00 का ड्राफ्ट नं0 ..... तिथि.....

**अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा देय शुल्क**

1. पंजीकरण शुल्क के लिये 3000/- रुपये का भुगतान देने का बैंक ड्राफ्ट नं0 ..... तिथि .....
2. वैरिफिकेशन शुल्क के लिए 2500/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट नं0 ..... तिथि .....
3. रुपये 25/- का बैंक का नाम ड्राफ्ट नं0 ..... तिथि.....
4. नियम 40 के अन्तर्गत रुपये 3000/- का बैंक ड्राफ्ट नं0 ..... तिथि.....
5. स्टेब्लिसमेण्ट फण्ड रुपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट नं0 ..... तिथि.....
6. 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों हेतु रू0 2000.00/15000.00 का ड्राफ्ट नं0 ..... तिथि.....

यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो उसका उल्लेख यहाँ अवश्य करें तथा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी से प्राप्त करके दाखिल करें।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

पत्र व्यवहार का पता

संलग्न प्रमाण-पत्र:-

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| हिन्दी.....                   | 1. |
| .....                         | 2. |
| .....                         | 3. |
| अंग्रेजी के बड़े अक्षरों..... | 4. |
| .....                         | 5. |
| .....                         |    |
| फोन नं0 .....                 |    |

**घोषणा**

मैं श्री .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....

निवासी .....

बार कौंसिल आफ उत्तरांचल का अधिवक्ता होने का नियमित पंजीकरण के लिए एक आवेदक निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ और निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका/चुकी हूँ।
  2. अपना नाम पंजीकृत होने की तिथि से साधारणतः उत्तराखण्ड बार कौंसिल के अधिकार से मैं नियमित रूप से विधि व्यवसाय करूँगा/करूँगी।
  3. शासन अथवा किसी अन्य विभाग में मैं नियुक्त नहीं हूँ।
  4. मैं कोई अन्य व्यापार अथवा कारोबार नहीं करता/करती हूँ।
  5. किसी राज्य की राज्य बार कौंसिल अथवा भारत के किसी अन्य न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिवक्ता पंजीकरण का मेरा आवेदन पत्र कभी अस्वीकार नहीं किया गया है।
  6. मैं भारतीय नागरिक हूँ।
  7. मैं पुनःलिखित घोषणा कर रहा/रही हूँ कि मैं अपनी योग्यता और अच्छे अपने ज्ञान से एक एडवोकेट के कार्य एवं व्यवहार को वस्तुतः ईमानदारी से निर्वाह करूँगा/करूँगी और पंजीकृत अधिवक्ताओं का व्यवहार विनियमित करने के लिए लागू उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में जारी किये गये आदेशों एवं बार कौंसिल द्वारा बनाये गये नियमों का भक्तिपूर्वक पालन करूँगा/करूँगी।
  8. मैं घोषित करता/करती हूँ कि भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा रखूँगा/रखूँगी।
  9. मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी सेवा में युक्त होने, व्यापार, कारोबार अथवा भिन्न वृत्ति करने पर अपना अधिवक्ता प्रमाण-पत्र बार कौंसिल को तुरन्त अभ्यापित कर दूँगा/दूँगी।
  10. मैं घोषित करता/करती हूँ कि विधि व्यवसाय के अपने साधारण स्थान अथवा उसके परिवर्तन की सूचना बार कौंसिल को दूँगा/दूँगी।
  11. मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं कभी नैतिक, नीचता या अस्पृश्यता के दोष में दंडित नहीं हुआ हूँ।
  12. मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध भारतीय दंड संहिता अथवा अन्य किसी एक्ट का कोई मुकदमा किसी भी फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही किसी आपराधिक केस में मेरी गिरफ्तारी हुई और न ही मेरे विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई विवेचना चल रही है।
  13. मैं घोषित करता/करती हूँ कि अधिवक्ता के रूप में बार कौंसिल द्वारा पंजीकृत किये जाने के बाद मेरे विरुद्ध (Moral Turpitude) के अन्दर आने वाला कोई भी आपराधिक वाद या एफ0आई0आर0 कायम होता है तो मैं उपरोक्त आपराधिक वाद से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट या यदि परिवाद कायम होता है तो परिवाद की प्रतिलिपि उत्तराखण्ड बार कौंसिल को उक्त तथ्य की जानकारी होने की तिथि से तीन माह के अन्दर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दूँगा इस बात को सुनिश्चित करूँगा कि परिवाद या एफ0आई0आर0 की प्रति बार कौंसिल को मिल गई है।
- (अ) मैं घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त परिवाद या मुकदमें में जो भी अन्तिम निर्णय होगा इस निर्णय की सत्य-प्रतिलिपि को भी निर्णय की तिथि से तीन माह के अन्दर बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड को सत्य-प्रतिलिपि के साथ रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करूँगा/करूँगी और सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि प्रति मिल गई है।
- (ब) मैं घोषित करता/करती हूँ कि अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के पश्चात मैं अपने जीवन यापन हेतु किसी अन्य व्यवसाय या नौकरी या अन्य प्रोफेशन को जीविकापार्जन के साधन के रूप में नहीं अपनाऊँगा/ अपनाऊँगी।
14. मैं निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि मैंने खण्ड 1 से खण्ड (12) में दी गई समस्त सूचना जो मेरे पंजीकरण से सम्बन्धित है, मेरे ज्ञान एवं विश्वास से सत्य है इसमें न कुछ छिपाया गया है और न कोई भाग असत्य है।
  15. मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैंने बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्मित खण्ड 6 में वर्णित चैप्टर 1 से चैप्टर 4 में दिये (पंजीकरण फार्म के साथ संलग्न) समस्त नियमों का भली-भाँति अध्ययन कर लिया है जिनका पालन पंजीकरण के बाद पूरी निष्ठा के साथ नियमित रूप से करूँगा/करूँगी।  
मैं स्थान .....  
मैं व्यवसाय (प्रेक्टिस) करना चाहता हूँ।  
स्थान.....  
दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

**चरित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र  
(प्रत्येक आवेदक द्वारा प्रेषणीय)**

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता  
हूँ। ये सच्चरित्र हैं और अधिवक्ता पंजीकरण होने योग्य एवं उपयुक्त हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

पदवी  
अधिवक्ता पंजीकरण संख्या

**कार्यालय का प्रतिवेदन**

आवेदक श्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....  
विश्वविद्यालय .....  
के स्नातक हैं तथा इस प्रकार ये सन् 1961 ई0 के एडवोकेट्स अधिनियम की धारा 24(1) खण्ड डी के उपलब्ध  
1 के अन्तर्गत अधिवक्ता होने के अधिकारी हैं।

पंजीकरण लिपिक

**प्रतिवेदन**

सन् 1961 के एडवोकेट्स अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत आवेदक को एक अधिवक्ता पंजीकृत कर लिया जाये।

तिथि .....

सचिव

**पंजीकरण समिति का आदेश**

(1) आवेदक श्री .....  
पुत्र/पत्नी/पत्नी श्री.....का नाम सन् 1961 ई0 के  
एडवोकेट्स अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत अधिवक्ता पंजीकरण कर लिया जाये/न किया जाये।

.....  
सदस्य

.....  
सदस्य

.....  
सदस्य

पंजीकरण प्रमाण-पत्र तैयार करने की तिथि .....

पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या.....

.....  
हस्ताक्षर

.....  
निरीक्षणकर्ता

## IDENTITY CARD APPLICATION FORM

To,

The Secretary,  
Bar Council of Uttarakhand.  
Tel, fax. +915942-233525



Sub: Issuance of Identity Card.

Sir,

I desire to have Identity Card as per the Rules framed by the Bar Council of Uttarakhand

I am sending herewith my tow latest passport size photographs in Court Dress (one affixed on this form & another on the slip) and photo copy of the Enrolment Intimation Letter/Sanad Certificate) The sum of Rs 200/- (Rupees Two Hundred Only) being the cost of Identity Card is also sent herewith in Cash/ money order.

My particulars are as under:

1. Name (In Block letter) .....
2. Father's Name (In Block letter) .....
3. Address (In Block letter) .....
- .....
- Mobile .....
4. Enrolment No. U.P.....U.K .....
5. Date of Registration.....
6. Date of Birth .....

-----  
Signature of the applicant

**स्टेट बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के समक्ष  
शपथ-पत्र (प्रारूप)**

**नोट:— किसी भी प्रकार के विश्राम वर्ष का शपथ-पत्र में स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें।**

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

निवासी.....यह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि

1. यह कि मैं जन्म से भारतीय नागरिक हूँ।
2. यह कि मेरी जन्म तिथि ..... है और मेरी आयु 21वर्ष से अधिक है।
3. यह कि मैं कभी किसी अपराध में दण्डित नहीं हुआ हूँ।
4. यह कि मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी एक्ट का कोई मुकदमा किसी भी फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही किसी अपराधिक केस में मेरी गिरफ्तारी हुई न ही मेरे विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई विवेचना चल रही है।

(यदि किसी अपराध का कोई मुकदमा पुलिस अथवा न्यायालय में विचाराधीन हो तो उसका स्पष्टीकरण दीजिए)

5. यह कि मैं इस समय किसी नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय में कार्यरत हूँ।
6. यह कि मैं कभी किसी नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय में कार्यरत नहीं था और न इस समय हूँ।

(यदि प्रार्थी किसी नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय में कार्यरत रहा है तो उसका विवरण दें और जिस स्थान पर रहा है, वहाँ सेवायोजन का चरित्र प्रमाण-पत्र दें तथा यह भी सत्यापित करें कि कैसे समाप्त हुई?)

7. यह कि मैंने इससे पूर्व किसी स्टेट बार कौंसिल अथवा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है और न ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुआ।
8. यह कि मैंने हाईस्कूल परीक्षा सन् ..... में उत्तीर्ण की है।
9. यह कि मैंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा सन् ..... में उत्तीर्ण की है।
10. यह कि मैंने स्नातक की परीक्षा सन् ..... में उत्तीर्ण की है।
11. यह कि मैंने विधि स्नातक की परीक्षा सन् ..... में उत्तीर्ण की है।

(यदि हाईस्कूल से लेकर आवेदन पत्र देने की तिथि तक की अवधि में प्रार्थी का किसी वर्ष विश्राम हो अथवा अनुत्तीर्ण हुआ हो तो उसका स्पष्टीकरण शपथ पत्र में उल्लिखित करें। )

12. यह कि मेरे हाईस्कूल प्रमाण-पत्र से लेकर विधि स्नातक के प्रमाण पत्र तक मेरे नाम तथा सरनेम में कोई विभिन्नता नहीं है।

(यदि हाईस्कूल से लेकर विधि स्नातक के प्रमाण-पत्रों में किसी प्रकार नाम की विभिन्नता है तो प्रार्थी इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण करें कि हाईस्कूल से लेकर विधि स्नातक सभी प्रमाण-पत्र उसी से ही सम्बन्धित हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में प्रार्थी का नाम 'रामकिशोर' उल्लिखित है तो यह स्पष्टीकरण कर देना चाहिये कि ये सभी प्रमाण पत्र उसी से सम्बन्धित हैं।)

13. यह कि अधिवक्ता के रूप में स्टेट बार कौंसिल द्वारा पंजीकृत किये जाने के बाद मेरे विरुद्ध **Moral Turpitude** के अन्दर आने वाला कोई भी अपराधिक वाद या एफ0आई0आर0 कायम होता है तो मैं उपरोक्त अपराधिक वाद से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट या यदि परिवाद कायम होता है तो परिवाद की प्रतिलिपि उत्तराखण्ड बार कौंसिल को उक्त तथ्य की जानकारी होने तिथि से तीन माह के अन्दर पंजीकृत डाक से प्रेषित कर दूंगा। इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि प्रति मिल गई है।

(अ) उपरोक्त परिवाद या मुकदमें में जो भी अन्तिम निर्णय होगा उस निर्णय की सत्य-प्रतिलिपि को भी निर्णय की तिथि से तीन माह के अन्दर स्टेट बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड को सत्य प्रतिलिपि के साथ पंजीकृत डाक से प्रेषित करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि परिवाद या एफ0आई0आर0 की प्रति स्टेट बार कौंसिल को प्रति मिल गई है।

(ब) यह कि अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के पश्चात मैं अपने जीवन यापन हेतु किसी अन्य व्यापार, व्यवसाय या नौकरी या अन्य प्रोफेशन को जीविकोपार्जन के साधन के रूप में नहीं अपनाऊंगा।

(स) यह कि शपथकर्ता अधिवक्ता के रूप में मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के प्रस्तुत नियम एवं माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेश के अनुक्रम में किसी भी संबद्ध बार एसोसिएशन में अपने मत का प्रयोग केवल 1 ही बार एसोसिएशन में करूंगा।

14. कोई विशेष उल्लेख।

यह कि शपथ-पत्र के उपरोक्त पैराग्राफ 1 से ..... तक मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है, इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। भगवान मेरी सहायता करे।

आज दिनांक ..... स्थान ..... पर सत्यापित किया।

## —:आवश्यक निर्देश:—

अधिवक्ता पंजीकरण के लिए दिये जाने वाले आवेदन-पत्र में निम्नलिखित बातों का होना अनिवार्य है।

1. आवेदक का नाम अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में एक हो।
2. प्रपत्र पर निर्दिष्ट सभी उपयुक्त स्थानों पर आवेदक के हस्ताक्षर हों।
3. आवेदन पत्र को शुल्क भुगतान के चालान की प्रति/झापट, पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, शपथ-पत्र, सादे पन्ने पर चार पासपोर्ट फोटो, हाईस्कूल- अंक तालिका, प्रमाण- पत्र, इण्टरमीडिएट- अंक तालिका, प्रमाण- पत्र, स्नातक- अंक तालिका, डिग्री और विधि (एल0एल0बी0) परीक्षाओं की अंक तालिका, डिग्री की स्व प्रमाणित छाया प्रति एवं अंत में रू0 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के कम में संलग्न करें।  
\* स्नातक एवं विधि स्नातक के प्रमाण पत्र न हों तो अंत कालीन प्रमाण-पत्र (जो कि प्रमाण-पत्र निर्गत होने की तिथि से 6 माह तक वैध होते हैं) की मूल प्रति संलग्न करें।
4. विद्यालयी/विश्वविद्यालयी सत्यापन हेतु हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र, इण्टरमीडिएट का प्रमाण-पत्र, स्नातक की डिग्री/अंतः कालीन डिग्री एवं विधि स्नातक की डिग्री/अंतः कालीन डिग्री की छायाप्रति फॉर्म के साथ जमा करायें।
5. यदि विधि स्नातक प्रमाण-पत्र प्राप्त न हुआ हो तो एल0एल0बी0 परीक्षा के अन्तःकालीन (प्रोविजनल) मूल प्रमाण पत्र एवं विधि स्नातक, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की मूल अंकतालिका एवं प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करें।
6. यदि हाईस्कूल, स्नातक और विधि स्नातक के मूल अथवा अन्तःकालीन प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र उपलब्ध न हो तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिणाम प्रदर्शित राजपत्र के उद्धरण, साथ में इस आशय का शपथ पत्र भी हो कि अमुक उद्धरण केवल आवेदन से ही सम्बन्धित है।
7. यदि आवेदक कभी नौकरी में रहा हो तो सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट), त्याग पत्र अथवा उन्मुक्ति (डिसचार्ज) के कारण नौकरी छोड़ने का मूल प्रमाण पत्र अधिकारीगण की मोहर सहित संलग्न कीजिए।
8. नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र दस रुपये के स्टाम्प पत्र पर होना चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप इस पृष्ठ के दूसरी ओर अंकित है। शपथ पत्र में विराम वर्ष का कारण सहित स्पष्ट उल्लेख करें।
9. रू0 500/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर संलग्न करें।
11. सामान्य अभ्यर्थी द्वारा देय शुल्क:- बैंक चालान अथवा झापट जो कि निम्न मदों में देय हों-

- (1) फार्म शुल्क 2000 /-रुपये बैंक चालान अथवा झापट "बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड" नैनीताल के नाम से देय होगा।
- (2) पंजीकरण शुल्क की अदयागी किसी भी बैंक में रुपये 6000/- (छः हजार रुपये मात्र) के चालान अथवा बैंक झापट द्वारा की जा सकती है जो " बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड" नैनीताल के नाम देय होगा।
- (3) प्रपत्रों के विद्यालयी/विश्वविद्यालयी सत्यापन हेतु रू0 2500/- बैंक चालान अथवा झापट जो कि "बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड 'रजिस्ट्रेशन वैरिफिकेशन एकाउंट नैनीताल'" के नाम पर देय हो।
- (4) रू0 150/- (एक सौ पचास रुपये मात्र) बैंक चालान अथवा झापट जो "बार कौंसिल ऑफ इण्डिया कलेक्शन फण्ड एकाउन्ट नैनीताल" के नाम देय होगा।
- (5) नियम 40 के अन्तर्गत रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये मात्र) बैंक चालान अथवा झापट जो " अखिल भारतीय बार कौंसिल अधिवक्ता कल्याणकारी समिति उत्तराखण्ड नैनीताल" के नाम देय होगा।
- (6) बीमा धनराशि के रूप में 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) बैंक चालान अथवा झापट जो " बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड स्टैब्लिसमेंट फण्ड फॉर एक्सीडेंटल एण्ड डेथ क्लेम एकाउंट नैनीताल" के नाम देय होगा।
- (7) यदि आवेदक कभी सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी में रहा हो तो निवृत्ति (रिटायरमेंट), त्याग पत्र अथवा उन्मुक्ति (डिसचार्ज) हुआ है तथा यदि आवेदक पंजीकरण फार्म जमा करने की तिथि तक 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो उसे 20,000/- रुपये का अतिरिक्त शुल्क चालान अथवा झापट के माध्यम से "बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड" नैनीताल के नाम देय होगा।

12. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा देय शुल्क:- बैंक चालान अथवा झापट जो कि निम्न मदों में देय हों-

- (1) फार्म शुल्क 2000 /-रुपये बैंक चालान अथवा झापट "बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड" नैनीताल के नाम से देय होगा।
- (2) पंजीकरण शुल्क की अदयागी किसी भी बैंक में रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये मात्र) के चालान अथवा बैंक झापट द्वारा की जा सकती है जो " बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड" नैनीताल के नाम देय होगा।
- (3) प्रपत्रों के विद्यालयी/विश्वविद्यालयी सत्यापन हेतु रू0 2500/- बैंक चालान अथवा झापट जो कि "बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड 'रजिस्ट्रेशन वैरिफिकेशन एकाउंट नैनीताल'" के नाम पर देय हो।
- (4) रू0 25/- (पच्चीस रुपये मात्र) बैंक चालान अथवा झापट जो "बार कौंसिल ऑफ इण्डिया कलेक्शन फण्ड एकाउन्ट नैनीताल" के नाम देय होगा।
- (5) नियम 40 के अन्तर्गत रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये मात्र) बैंक चालान अथवा झापट जो " अखिल भारतीय बार कौंसिल अधिवक्ता कल्याणकारी समिति उत्तराखण्ड नैनीताल" के नाम देय होगा।
- (6) बीमा धनराशि के रूप में 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) बैंक चालान अथवा झापट जो " बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड स्टैब्लिसमेंट फण्ड फॉर एक्सीडेंटल एण्ड डेथ क्लेम एकाउंट नैनीताल" के नाम देय होगा।
- (7) यदि आवेदक कभी सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी में रहा हो तो निवृत्ति (रिटायरमेंट), त्याग पत्र अथवा उन्मुक्ति (डिसचार्ज) हुआ है तथा यदि आवेदक पंजीकरण फार्म जमा करने की तिथि तक 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो उसे 20,000/- रुपये का अतिरिक्त शुल्क चालान अथवा झापट के माध्यम से "बार कौंसिल ऑफ उत्तराखण्ड" नैनीताल के नाम देय होगा।



**नोट—**

1. सभी ड्राफ्ट एस0बी0आई0 हाईकोर्ट ब्रान्च नैनीताल के पक्ष में देय हो।
2. अभ्यर्थी ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम व पता अवश्य लिखे।
3. फार्म में चिपकायी गयी फोटो जो सफेद शर्ट, काली टाई व काले कोट या बन्द गले का कोट या शेरवानी में तथा महिलाओं हेतु सफेद साड़ी एवं काले कोट हो तथा किसी प्रथम श्रेणी के मजि0/जज अथवा बार कौंसिल के निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इस फोटो के अतिरिक्त 4 फोटो एक सफेद कागज पर चिपकाकर नत्थी करें।
10. चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रथम श्रेणी के मजि0, जज बार कौंसिल आफ उत्तराखण्ड के निर्वाचित सदस्य अथवा दस वर्ष से अधिक अवधि के पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि चरित्र प्रमाण पत्र अधिवक्ता द्वारा दिया गया हो तो उनके पूर्ण हस्ताखर तथा पंजीकरण की संख्या का स्पष्ट उल्लेख हो।
11. आवेदक अपना पता लिखा पोस्ट कार्ड संलग्न करें। अपना पता साफ शब्दों में लिखें। (केवल उन आवेदकों हेतु जो रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन कर रहे हों)।
12. पंजीकरण के पश्चात उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, देहरादून द्वारा संचालित "अधिवक्ता भविष्य निधि योजना" की सदस्यता हेतु आवेदन करें। योजना का लाभ उठायें।  
नोट— सभी प्रपत्रों को ठीक से संलग्न कर कार्यालय में जमा करें।  
नोट— माह के प्रत्येक रविवार एवं द्वितीय शनिवार तथा सरकारी अवकाश के दिन कार्यालय बन्द रहेगा।

सचिव  
स्टेट बार कौंसिल आफ  
उत्तराखण्ड

Extract of relevant part framed by the Bar Council of Uttaranchal  
(As amended upto 31st July 1995)

PART-VI

RULES GOVERNING ADVOCATES

CHAPTER-I

RESTRICTIONS ON SENIOR ADVOCATES

(Rules under Sections 16(3) and 49(1)(g) of the Act)

Senior Advocates shall, in the matter of their practice of the profession of law mentioned in Section 30 of the Act, be subject to the following restrictions:

(a) A Senior Advocate shall not file a vakalatnama or act in any Court, or Tribunal, or before any person or other authority mentioned in Section 30 of the Act.

**Explanation:** "To Act" means to file an appearance or any pleading or application in any court, to Tribunal, or before any person or other authority mentioned in Section 30 of the Act, or to do any act other than pleading required or authorised by law to be done by a party in such Court, or Tribunal, or before any person or other authority mentioned in the said Section either in person or by his recognised agent or by an advocate or an attorney on his behalf.

(b) (i) A Senior Advocate shall not appear without an Advocate on Record in the Supreme Court or without an Advocate in Part II of the State Roll in any court, or Tribunal, or before any person or other authorities mentioned in Section 30 of the Act.

(ii) Where a Senior Advocate has been engaged prior to the coming into force of the Rule in this Chapter, he shall not continue thereafter unless an Advocate in Part II of the State Roll is engaged along with him. Provided that a Senior Advocate may continue to appear without an Advocate in Part II of the State Roll in cases in which he had been briefed to appear for the prosecution or the defence in a criminal case, if he was so briefed before he is designated as a Senior Advocate or before coming into operation of the rules in this Chapter as the case may be.

(c) He shall not accept instructions to draft pleading or affidavits, advice on evidence or to do any drafting work of an analogous kind in any Court or Tribunal, or before any person or other authority mentioned in Section 30 of the Act or undertake conveyancing work of any kind whatsoever. This restriction however shall not extend to setting any such matter as aforesaid in consultation with an Advocate in Part II of the State Roll.

(cc) A Senior Advocate shall, however, be free to make concessions or give undertakings in the course of arguments on behalf of his clients on instructions from the Junior advocate.

(d) He shall not accept directly from a client any brief of instructions to appear in any Court or Tribunal, or before any person or other authority in India.

(e) A Senior Advocate who has acted as Advocate (Junior) in a case, shall not after he has been designated as a Senior Advocate advise on grounds of appeal in a Court of Appeal or in the Supreme Court, except with an Advocate as aforesaid.

(f) A Senior Advocate may in recognition of the services rendered by an Advocate in Part II of the State Roll appearing in any matter pay him a fee which he considers reasonable.

CHAPTER-II

Standards of Professional Conduct and Etiquette

(Rules under Section 49 (1) (c) of the Act read with the Proviso thereto)

Preamble

An advocate shall, as a member of the Bar, comport himself in a manner befitting his status as an officer of the Court, a privileged member of the community and a gentleman, bearing in mind that what may be lawful and moral for a person who is not a member of the Bar, or for a member of the Bar in his non-professional capacity may still be improper for an Advocate. Without prejudice to the generality of the foregoing obligation, an Advocate shall fearlessly uphold the interests of his client, and in his conduct conform to the rules hereinafter mentioned, both in letter and in spirit. The rules hereinafter mentioned contain a code of conduct and etiquette adopted as general guides; yet the specific mention thereof shall not be construed as a denial of the existence of other equally imperative though not specifically mentioned.

Section I-Duty to the Court

1. An Advocate shall, during the progress of his case and while otherwise acting before a Court, conduct himself with dignity and self-respect. He shall not be servile and whenever there is proper ground for serious complaint against a Judge or a Court, it shall be his right and duty to submit his grievance to proper authorities.
2. An Advocate shall, in relation towards the Courts, respect a respectful attitude, bearing in mind that the dignity of the Judicial office is essential for the survival of free society.
3. An Advocate shall not influence the decision of a Court by any illegal or improper means. Private communication with a Judge relating to a pending case are forbidden.
4. An Advocate shall use his best efforts to restrain and prevent his client from resorting to sharp or unfair practices or from doing anything in relation to the court, opposing counsel or parties which the Advocate himself ought not to do. An advocate shall refuse to represent the client who persists in such improper conduct. He shall not consider himself a mere mouth-piece of the client and shall exercise his own judgement in the use of restrained language in correspondence, avoiding acrimonious attacks in pleadings, and using temperate language during arguments in Court.
5. An Advocate shall appear in Court at all times only in the prescribed dress, and his appearance shall always be presentable.

6. An Advocate shall not enter **appearance**, act, plead or practise in any way before a Court, Tribunal or Authority mentioned in Section 30 of the Act, if the sole or any member thereof is related to the Advocate as father, grandfather, son, grand-son, uncle, brother, nephew, first cousin, and wife, mother, daughter or Institution or Society or corporation. "Executive Committee", by whatever name it may be called, shall include any Committee or body of **persons** which, for the time being, is vested with the general management of the affairs of the organization or Institution, Society or corporation.  
For the purposes of this rule, Court, Bench or Tribunal in which above mentioned relation of the Advocate is a Judge, Member or the Presiding Officer.
7. An Advocate shall not wear bands or gown in public places other than in Court except on such ceremonial occasions and as such places in the Bar Council of India or the Court may prescribe.
8. An Advocate shall not appear in or before any Court or Tribunal or any other authority for **any** organization or institution, society or corporation, if he is a member of the Executive Committee of such organization or Institution or Society or corporation. "Executive Committee", by whatever name it may be called, shall include any Committee or body of **persons** which, for the time being, is vested with the general management of the affairs of the organization or Institution, Society or corporation.  
Provided that this rule shall not apply to such a member appearing in a **case** or with **a fee** on behalf of a Bar Council, Incorporated Law Society or a Bar Association.
9. An Advocate should not act or plead in any matter in which he is **interested**.

Illustration:

- I. He should not act in a bankruptcy petition when he himself is also a creditor of the bankrupt.
  - II. He should not accept a brief from a Company of which he is Director.
10. An Advocate shall not stand as a surety, or certify the amount of a surety for the purpose of any legal proceedings.

Section II Duty to the Client

11. An Advocate is bound to accept any brief in a Court, or Tribunal or before any other authority in or before which he proposes to practise at a fee consistent with his standing at the Bar and the nature of the case. Special circumstances may justify his refusal to accept a particular brief.
12. An Advocate shall not ordinarily withdraw from engagements, once accepted, without sufficient cause and unless he has given notice in writing to the client. Upon his withdrawal from a case, he shall refund a **part** of the fee "has not been earned."
13. An Advocate should not accept a brief to appear in a case in which he is a witness, and if being engaged in a case, it becomes apparent that he is a witness on a material question of fact, he should not continue to appear as an Advocate if he can retire without jeopardising his client's interests.
14. An Advocate shall, at the commencement of his engagement and during the continuance thereof, make all such full and frank disclosures to his client relating to his connection with the parties and any interest in or about the controversy as are likely to affect his client's judgment in either engaging him or continuing the engagement.
15. It shall be the duty of an Advocate fearlessly to uphold the law, of his client by all fair and honourable means without regard to any unpleasant consequence, to defend **any** person accused of a crime **in** his personal opinion of his guilt of the accused, bearing in mind that his loyalty is to the law which requires that no man should be convicted without adequate evidence.
16. An Advocate appearing for the prosecution of a criminal offence shall so conduct the prosecution that it does not lead to the conviction of the innocent. The **use** of material capable of establishing the innocence of the accused shall be scrupulously avoided.
17. An Advocate shall not, directly or indirectly, commit a breach of the obligation imposed by Section 126 of the Indian Evidence Act.
18. An Advocate shall not, at any time, be a party to fomenting of litigation.
19. An Advocate shall act on the instructions of any person other than his client or his authorised agent.
20. An Advocate shall not stipulate for a fee contingent on the result of litigation or agree to share the proceeds thereof.
21. An Advocate shall not buy or traffic in or stipulate for or agree to receive any share or interest in any actionable claim. Nothing in this rule shall apply to stocks, shares and debentures of government securities, or to any instruments which for the time being by law or custom, negotiable or to any mercantile document of title to goods.
22. An Advocate shall not, directly or indirectly, bid for or purchase, either in his own name or in any other name, for his own benefit or for the benefit of any other person, any property sold in the execution of a decree or order in any suit, appeal or other proceeding in which he was in any way professionally engaged. This prohibition, however, does not prevent an Advocate from bidding for or purchasing for his client any property which his client may himself legally bid for or purchase, provided the Advocate has previously authorised in writing in that behalf.
23. An Advocate shall not adjust fees payable to him by his client against his own personal liability to the client, which liability does not arise in the course of his employment as an Advocate.
24. An Advocate shall not do anything whereby he abuses or takes advantage of the confidence reposed in him by his client.
25. An Advocate should keep accounts of the client's money entrusted to him, and the account should show the amounts received from the client on his behalf, the expenses incurred for him and debits made on account of fees with respect to cases and any other **necessary** particulars.

---

1. Dt. of this Rules 20.2.91 Proviso added by rescission no. 11191.

26. Where moneys **are** received from or on account of a client, the entries in the accounts should contain a reference **to** whether the amounts have been received for fee, or **costs, expenses, and** during the course of the proceedings, no Advocate shall, except with the consent in writing of the client concerned, be at liberty to divert any portion of the expenses towards **family**.
27. Where any amounts are received or given to him on behalf of the client, the date of each receipt must be noted in the client's account, as early **as possible**.
28. After the termination of the proceeding, the Advocate shall be at liberty to **propose** towards the settled amount due to him, any sum remaining unexpended out of the amount paid **or** lent to him for expenses. Any amount that has come into his hands in that proceeding.
29. Where the fee has been left unsettled, the Advocate shall be entitled to deduct out of any moneys of the client remaining in his hands, at the termination of the proceeding for which **he had been** engaged, the amount payable under the rules of the Court, in force at the time being, or by then settled and the balance, if **any**, shall be refunded to the client.
30. A copy of the client's account shall be furnished to him on demand provided the necessary copying charge is paid.
31. An Advocate shall not enter into arrangements whereby funds in his hands are converted into loans.
32. An Advocate shall not lend money to his client for the purpose of any action or legal **proceedings** in which he is **engaged** by his client.

**Explanation :** An Advocate shall not be held guilty for a breach of this rule, if in the course of a **pending suit or proceeding**, and without any arrangement with the client **in respect of the same, the Advocate** is compelled by the Court to make a payment to the court on account of the client for the progress of the suit or proceeding.

33. An Advocate who has, at any time advised in connection with the institution of a suit, **appeal** or other matter or has drawn pleadings, or acted for a party shall not act, appear or plead for the opposite party.

#### Section III-Duty to Opponent

34. An Advocate shall not in any way communicate or negotiate upon the subject matter of controversy with any party represented by an Advocate except through that Advocate.
35. An Advocate shall do his best to carry out all legitimate promises made to the opposite party even though not reduced to writing or enforceable under the rules of the Court.

#### Section IV-Duty to Colleagues

38. An Advocate shall not solicit work or advertise, either directly or indirectly, whether by circulars, advertisements, touts, personal communication, interviews not warranted by **personal relations**, furnishing or inspiring newspaper comments or producing his photograph to be published in connection with cases in which he has been engaged or concerned. His sign-board or name-plate should be of a reasonable size. The sign-board or name-plate to a law firm should not indicate that he is or has been President or Member of a Bar Council or of any Association or that he has been associated with any person or organisation or with any particular cause or matter or that he is engaged in any particular type of work or that he has been a Judge or an advocate general.
37. An Advocate shall not permit his professional services or his name to be used in aid of or to make possible, the unauthorised practice of law by any agency.
38. An Advocate shall not accept a **fee** less than the fee taxable under the rules when the client is **able** to pay the same.
39. An Advocate shall not enter appearance in any case in which there is already a vakalat or memo of appearance filed by an Advocate engaged for a party except with his consent; **In case** such consent is not produced he shall apply to the Court stating reasons *Why* the said consent should not be produced and **he** shall appear *only* after obtaining the permission of the Court.

#### Section IV-A

40. Every Advocate borne on the rolls of the State Bar Council shall pay to the State Bar Council a sum of Rs. 90/- every third year commencing from 1st April, 1993 along with a statement of particulars as given in the form set out at the end of these Rules, the first payment to be made on or before 1st April, 1993 or such extended time as notified by the Bar Council of India or the concerned State Bar Council.  
Provided further however that an Advocate shall be at liberty to pay in lieu of the payment of Rs. 90/- every three years a consolidated amount of Rs. 300/-. This will be a life time payment to be kept in the fixed deposit by the concerned State Bar Council and interest to be used for the purpose of the rule. However, payment made by the concerned Advocate before this consolidated payment shall be exclusive of it and no credit shall be given for the payment, but those advocates who have paid consolidated amount of Rs. 200/- only as a consolidated Rs. 100/- will be required to pay

**Explanation 1 :** Statement of particulars as required by rule 40 in the form set out shall require to be submitted *only* once in three years.

**Explanation 2 :** All Advocates who are in actual practice and not drawing salary or not in full time service and not drawing salary from their respective employers are only required to pay the amount referred to in this rule.

**Explanation 3 :** This rule will be effective from 1.4.1994 and for period prior to this Advocates will continue to be covered by old Rule.

11. (1) The sums so collected by the State Bar Council in accordance with Rule 40 shall be deposited in a special account known as "State Bar Council of India Advocates Welfare Fund for the State" and shall be deposited in the bank as provided hereunder.

- (2) The Bar Council of India Advocates Welfare Fund Committee for the State shall remit 20% of the total amount collected and credited to its account, to the Bar Council of India by the end of every month which shall be credited by the Bar Council of India and the Bar Council of India shall deposit the said amount in a separate fund to be known as 'BAR COUNCIL OF INDIA ADVOCATES WELFARE FUND'. This fund shall be managed by the Welfare Committee of the Bar Council of India in the manner prescribed from time to time by the Bar Council of India for the Welfare of the Advocates.
- (3) This rest 80% of the total sum so collected by the Bar Council of India Advocates Welfare Fund Committee for the State under Rule 41(1) shall be utilised for the welfare of advocates in respect of Welfare Schemes sponsored by the respective State Bar Councils and this fund shall be administered by the Advocates Welfare Committee for the State which shall submit a report annually to the Bar Council of India.
42. If any advocate fails to pay the aforesaid sum within the prescribed time as provided under rule 40, the Secretary of the State Bar Council shall issue a notice to show cause within a month why his right to practice be not suspended. In case the advocate does not pay the amount or fails to show sufficient cause, a Committee of three members constituted by the State Bar Council in this behalf may pass an order suspending the right of the advocate to practise. Provided that the order of suspension shall cease to be in force when the advocate concerned pays the amount along with a late fee of Rs. 60/- and obtains a certificate in this behalf from the State Bar Council.
43. An advocate who has been convicted of an offence mentioned under section 24A or the Advocates Act or has been declared insolvent or has taken full or part time service or engaged in business or any avocation inconsistent with his practice as an Advocate or has incurred any disqualification mentioned in the Advocates Act or the rules made thereunder, shall send a declaration to the effect to the respective State Bar Council in which the Advocate is to show sufficient cause for not filling such declaration. On provided therefor, the Committee constituted by the State Bar Council under rule 42 may pass orders suspending the right of the advocate to practise. Provided that it shall be open to the Committee to condone the delay on an application being made in this behalf. Provided further that an advocate who had after the date of his enrolment and before the coming into force of this rule, become subject to any of the disqualifications mentioned in this rule, shall within a period of ninety days of the coming into force of this rule send declaration referred to in this rule to the respective State Bar Council in which the Advocate is enrolled and on failure to do so by such Advocate all the provisions of this rule would apply.
44. An appeal shall lie to the Bar Council of India at the instance of an aggrieved advocate within a period of thirty days from the date of the order passed under rules 42 and 43.
- 44A. (1) There shall be a Bar Council of India Advocates Welfare Committee consisting of five members elected from amongst the members of the Council. The term of the members of the committee shall be co-extensive with their term in the Bar Council of India.
- (2) (i) Every State Council shall have an Advocate Welfare Committee known as Bar Council of India Advocates Welfare Committee for the State.
- (ii) The Committee shall consist of member Bar Council of India from the State concerned who shall be the Ex-Office Chairman of the Committee and two members elected from amongst the members.
- (iii) The Secretary of the State Bar Council concerned shall act as Ex-Office Secretary of the Committee.
- (iv) The term of the Secretary, Bar Council of India in the Committee shall be co-extensive with his term in the Bar Council of India.
- (v) The term of members elected from the State Bar Council shall be two years.
- (vi) Two members of the Committee will form a quorum for any meeting of the Committee.
- (3) Every State Bar Council shall open an account in the name of the Bar Council of India Welfare Committee for the State, in any Nationalised Bank.
- (4) No amount shall be withdrawn from the Bank unless that cheque is signed by the Chairman of the Welfare Committee and its Secretary.
- (5) The State Bar Council shall implement Welfare Scheme approved by the Bar Council of India through Advocates Welfare Committee as constituted under sub-clause (2)(i). The State Bar Councils may suggest suitable modifications in the Welfare Schemes or suggest more schemes, but such modifications or such suggested schemes shall have effect only after approval by the Bar Council of India.
- (6) The State Bar Council shall maintain separate account in respect of the Advocate Welfare Fund which shall be audited annually along with other accounts of the State Bar Council and send the same along with Auditors Report to the Bar Council of India.
- 44:1 The Bar Council of India shall utilise the funds received under Rule 41(2) in accordance with the schemes which may be framed from time to time.

FORM UNDER RULE 40

The Bar Council .....

.....●.....

Dear Sirs,

- (1) I am enclosing herewith a Postal order/Bank Draft/Cash for.....being the payment under Rule-40, Chapter II, Part VI of the Rules of the Bar Council of India.
- (2) I am enrolled as an Advocate on the Roll of your State Bar Council.
- (3) I am ordinarily practising at .....In the territory/State of
- (4) I am a member of the Bar Association/not a member of any Bar Association.
- (5) My present address is .....

SIGNATURE

NAME IN BLOCK LETTERS

ENROLLMENT NO.....

DATED:

PLACE:

Receives a sum of Rs. 30/- from.....towards payment under Rule-40, Chapter II, Part VI of the Rules of the Bar Council of India by way of Postal Order/Bank Draft/Cash on.....

SECRETARY

BAR COUNCIL OF.....

DATED:

PLACE:

Section V-Outy In Imparting training

46 It is improper for an Advocate to demand or accept fee or any premium from any person as a consideration for imparting training in law under the rules prescribed by a State Bar Council to enable such person to qualify for enrollment under the Advocates Act, 1961.

Section VI-Duty to Render Legal Aid

46 Every Advocate shall in the practice of the profession of law bear in mind that anyone genuinely in need of a lawyer is entitled to legal assistance even though he cannot pay for it fully or adequately and that within the limits of an Advocate's economic condition, free legal assistance to the indigent and oppressed is one of the highest obligations an Advocate owes to society.

Section VII-Restriction on other Employments

47 An Advocate shall not personally engage in any business; but he may be a sleeping partner in a firm doing business provided that, in the opinion of the appropriate State Bar Council, the nature of the business is not inconsistent with the dignity of the profession.

48 An Advocate may be Director or Chairman of the Board of Directors of a company with or without any ordinary sitting fee, provided none of his duties are of an executive character, An Advocate shall not be a Managing Director or a Secretary of any company.

49 An Advocate shall not be a full-time salaried employee of any person, government, firm, corporation or concern, so long as he continues to practise, and shall, on taking up any such employment, intimate the fact to the Bar Council on whose roll his name appears and shall thereupon cease to practice as an Advocate if he continues in salaried employment. Nothing in this rule shall apply to a Law Officer of the Central Government of a State or of a Public Corporation or body with Section 24 (1) (e) of the Act dealing with his being a full-time salaried employee.

Nothing in this rule shall apply to a Law Officer of the Central Government of the State or of any Public Corporation or body constituted by statute who is entitled to be enrolled under the rules of his State Bar Council made under Section 28 (2) (d) read with Section 24 (1) (e) of the Act despite his being a full-time salaried employee.

Law Officer for the purpose of this Rule means a person who is designated by the terms of his appointment and who, by the said terms, is required to act and/or plead in Courts on behalf of his employer.

50 An Advocate who has inherited, or succeeded by survivorship to, a family business may continue it, but may not personally participate in the management thereof. He may continue to hold a share with others in any business which has descended to him by survivorship or inheritance or by will, provided he does not personally participate in the management thereof.

51 An Advocate may review Parliamentary Bills for a remuneration, edit legal text books at a salary, do press-cutting for newspapers, coach pupils for legal examination, set and examine question papers; and subject to the rules against advertising and full-time employment, engage in broadcasting journalism, lecturing and teaching subjects, both legal and non-legal.

52 Nothing in these rules shall prevent an Advocate from accepting, after obtaining the consent of the State Bar Council, part-time employment provided that in the opinion of the State Bar Council the nature of the employment does not conflict with his professional work and is not inconsistent with the dignity of the profession. This rule shall be subject to such directions, if any, as may be issued by the Bar Council of India from time to time.

CHAPTER • III  
(Conditions for right to practice)  
(Rules under Section 49 (1) (eh) of the Act)

1. Every Advocate shall be under an obligation to see that his name appears on the roll of the State Council within whose jurisdiction he ordinarily practices.

PROVIDED that if an advocate does not apply for transfer of his name to the roll of the State Bar Council within whose jurisdiction he is ordinarily practising within six months of the start of such practice, it shall be deemed that he is guilty of professional misconduct within the meaning of section 35 of the Advocates Act.

2. An Advocate shall not enter into a partnership or any other arrangement for sharing remuneration with any person or legal Practitioner who is not an Advocate.

3. Every Advocate shall keep informed the Bar Council on the roll of which his name stands, of every change of his address.

4. The Council or a State Council can call upon an advocate to furnish the name of the State Council on the roll of which his name is entered, and can for other particulars.

5. (1) An Advocate who voluntarily suspends his practice for any reason whatsoever, shall intimate by registered post to the State Bar Council on the rolls of which his name is entered, of such suspension together with his certificate of enrollment in original.

(2) Whenever any such advocate who has suspended his practice desires to resume his practice, he shall apply to the Secretary of the State Bar Council for resumption of practice, along with an affidavit stating whether he has incurred any of the disqualifications under section 24A, Chapter III of the Act during the period of suspension.

(3) The Enrollment Committee of the State Bar Council may order the resumption of his practice and return the certificate to him with necessary endorsement if the Enrollment Committee is of the view that the Advocate has not incurred any of the disqualifications the Committee shall refer the matter under proviso to Section 28 (1) of the Act.

(4) On suspension and resumption of practice the Secretary shall act in terms of Rule 24 of Part IX.

6. (1) An Advocate whose name has been removed by order of the Supreme Court or the High Court or the Bar Council as the case may be, shall not be entitled to practice the profession of law either before the Court and authorities mentioned under Section 30 of the Act, or in chambers, or otherwise.

(2) An Advocate who is under suspension, shall be under same disability during the period of such suspension as an Advocate whose name has been removed from the roll.

7. An officer after his retirement or otherwise ceasing to be in service shall not practice for a period of two years in the area in which he exercised jurisdiction for a period of 3 years before his retirement or otherwise ceasing to be in service.

RESOLVED that nothing in these Rules shall prevent any such person from practising in any Court or tribunal or authority of superior jurisdiction to one in which he held office.

Explanation: 'Officer' shall include a Judicial Officer or authority as referred to in Section 30 of the Act.

'Area' shall mean area in which the person concerned is exercising jurisdiction.

8. No Advocate shall be entitled to practice if in the opinion of the Council he is suffering from such contagious disease as makes the practice of law a hazard to the health of others. This disqualification shall last for such period as the Council directs from time to time.

CHAPTER-IV  
FORM OF DRESSES OR ROBES TO BE WORN BY ADVOCATES  
(Rules under section 49 (1) (gg) of the Act)

Advocates appearing in the Supreme Court, High Court, Subordinate Courts, Tribunals or Authorities shall wear the following as part of their dress which shall be sober and dignified :-

I. ADVOCATES OTHER THAN LADY ADVOCATES

(a) a black buttoned up coat or jacket, black shirt and white bands with Advocates' Gowns, or

(b) a black open breast coat, white shirt, white collar, stiff or soft, and white bands with Advocates' Gowns. In either case long trousers (white, black or grey) or Dhoti.

II. LADY ADVOCATES

(a) Black and full or half sleeve Jacket or blouse, white collar stiff or soft, with white bands and Advocates' Gowns.

White blouse, with or without collar, with white bands and with a black open breast coat.

OR

(b) Saree or long skirt (White or black or any mellow or subdued colour without any print or design) or Flare (white, black or black striped or grey) or Punjabi dress churidar-Kurta or salwar-kurta with or without dupatta) white or black.

Provided that the wearing of Advocates' gown shall be optional except when appearing in the Supreme Court or High Court. [Provided further that in courts other than the Supreme Court, High Court, Session Court or City Civil Court a black tie may be worn instead of bands.]